UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**

The Indian EXPRESS | THE HINDU | pib PRESS INFORMATION BUREAU

23 SEPTEMBER

COMPQETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD STAY PREPARED

Result Mitra
हार तब नहीं होती
जब आप गिर जाते हैं,
हार तब होती है जब आप
उठने से इंकार कर देते हैं।
Small Steps Big Dreams
UPSC
STUDY
DISCIPLINE
SUCCESS
Better Than Yesterday
Dream Plan Study Achieve

आज क्या पढ़ेंगे?

- Ayurveda Day
- Women Farmer
- महत्वपूर्ण तथ्य

Social Welfare

11वां आयुर्वेद दिवस

स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद

- 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भारत अपनी 5,000 वर्ष पुरानी इस चिकित्सा पद्धति को साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक शोध के माध्यम से दैनिक और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा बनाने के एक दशक का उत्सव मना रहा है।
- आज देश भर के सरकारी क्लीनिक और अस्पताल नियमित चिकित्सा देखभाल के साथ-साथ आयुर्वेदिक उपचार भी प्रदान कर रहे हैं।
- मुफ्त ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श, बीमा कवरेज और उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान इन प्राचीन आरोग्य पद्धतियों को सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ बना रहे हैं।
- मजबूत वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि स्वस्थ भविष्य के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान किस प्रकार एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

आयुर्वेद: समग्र जीवन शैली की बुनियाद

- आयुर्वेद जीवन का एक विज्ञान है जो 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी जड़ें ऋग्वेद से जुड़ी हैं। आयुर्वेद शब्द आयु (जीवन) और वेद (विज्ञान) से मिलकर बना है। इसका मूल उद्देश्य 'स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं, आतुरस्य विकार प्रशमन' है। इसका मतलब है- स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमार व्यक्ति के विकार (रोग) को दूर करना।
- आयुर्वेद सच्ची स्वास्थ्य स्थिति को चयापचय तत्वों के सामंजस्यपूर्ण संतुलन के रूप में परिभाषित करता है। इस संतुलन के लिए जैव-ऊर्जा (दोष), चयापचय अग्नि (अग्नि), शारीरिक ऊतकों (धातु) और अपशिष्ट निष्कासन (मल) के साथ-साथ एक शांत आत्मा (आत्मा), मस्तिष्क (मानस) और इंद्रियों (इंद्रियों) के बीच इष्टतम तालमेल आवश्यक होता है।
- चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में वर्णित वनस्पतियों, पशु उत्पादों और खनिजों के औषधीय एवं चिकित्सीय गुणों का उपयोग करते हुए आयुर्वेद आज भी अपनी प्राचीनता के साथ आधुनिक प्रासंगिकता बनाए हुए है। इस विज्ञान का मुख्य सिद्धांत यह है कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का अपने आस-पास की दुनिया के साथ पूरी तरह से तालमेल होना।
- सरकार इस विरासत को सम्मान और बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक संतुलन को प्रतिबिंबित करने वाले शरद विषुव के अवसर पर हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाती है। बेहतर कल के लिए आयुर्वेद की थीम के अंतर्गत सरकार पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा को पुनर्जीवित करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति का क्रियान्वयन कर रही है।

स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण

- सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से आयुर्वेद समेत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा मुख्यधारा की सार्वजनिक चिकित्सा में उनका एकीकरण कर रही है। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित ये दोनों राष्ट्रीय मिशन देश भर में आयुष क्लीनिक, अस्पताल, विभाग और सामुदायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रहे हैं।
- एनएएम देश में आयुष स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और एकीकरण को गति दे रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों में आयुष स्वास्थ्य सेवा को शामिल करने के लिए एनएएम के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6,406.99 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।

टेलीमेडिसिन

- सरकार 'ई-संजीवनी' नाम की एक मुफ़्त टेलीमेडिसिन सेवा देती है, जिसका फ़ायदा 50 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ उठा चुके हैं। पारंपरिक चिकित्सा के अलावा, 'ई-संजीवनी' आयुष ओपीडी सेवाएँ भी देती है, जिससे मरीज़ सीधे इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आयुर्वेद (और अन्य आयुष सेवाओं) के विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं।

स्वास्थ्य बीमा

- सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत आयुष उपचारों को शामिल करने के लिए बीमा नीतियों को अपडेट किया है। वर्ष 2024 में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने अनिवार्य किया कि सभी बीमा कंपनियों को बोर्ड द्वारा स्वीकृत अंडरराइटिंग नीतियों (जोखिम मूल्यांकन के नियम) के तहत आयुर्वेद सहित चिकित्सा की सभी पद्धतियों को कवर करने वाले उत्पाद या ऐड-ऑन प्रदान करना आवश्यक है।

WHO के आईसीडी-11 मॉड्यूल में आयुर्वेद का समावेश

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण के 11वें संशोधन (आईसीडी-11) के मॉड्यूल में शामिल किए जाने के कारण आयुर्वेद की शब्दावली को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। इस कदम से दुनिया भर के चिकित्सक अब मानक कोड का उपयोग करके एएसयू (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) निदान को दर्ज करने में सक्षम होंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच एक समान अर्थ समझा जा सकेगा। यह बीमा प्रदाताओं के लिए आयुष उपचारों की प्रक्रिया, स्वीकृति और प्रतिपूर्ति को आसान बनाता है, साथ ही अनुसंधान एवं विकास, नीति-निर्माण और भविष्य के लिए रोग-नियंत्रण रणनीतियाँ तैयार करने में मदद मिलेगी।

आयुर्ज्ञान योजना

- इन प्रयासों के केंद्र में आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 में शुरू की गई 'आयुर्ज्ञान' योजना अहम है, जो अनुसंधान एवं विकास पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 34 परियोजनाओं में कुल 17.79 करोड़ रुपये के अनुसंधान निधि पूल में से आधे से अधिक हिस्सा आयुर्वेद का है, जिसे 17 समर्पित परियोजनाओं के लिए 9.38 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
- वर्ष 2026 की शुरुआत तक, 11 विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी, जिनमें से छह परियोजनाओं का फोकस पांच प्रमुख एकल आयुर्वेदिक वनस्पतियों के लिए सुरक्षा और असर से जुड़े दस्तावेज़ तैयार करने पर था। ये प्रयास बढ़ती अकादमिक उपलब्धियों को दर्शाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2014-15 से 2025-26 के बीच 33 आयुर्वेद विशिष्ट प्रकाशन और 2001-02 से अब तक कुल 77 शोध प्रकाशन सामने आए हैं।

आयुर स्वास्थ्य योजना

- आयुर्ज्ञान योजना के पूरक के रूप में 'आयुर स्वास्थ्य योजना' (2021-2026) शुरू की गई, जो आयुष नैदानिक और औषधि अनुसंधान, शिक्षा, सार्वजानिक स्वास्थ्य पहलों तथा सुविधाओं को 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में अपग्रेड करने के लिए सरकारी या गैर-लाभकारी आयुष संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- 2025 के अंत तक सहायता प्राप्त 25 परियोजनाओं में से 22 परियोजनाएं आयुर्वेद हस्तक्षेपों पर केंद्रित थीं या उनमें आयुर्वेद को शामिल किया गया था। इस योजना के तहत 28 विशेष उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें से 22 केंद्र आयुर्वेद-केंद्रित अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।

'स्पार्क' कार्यक्रम

- आयुर्वेद अनुसंधान ज्ञान छात्रवृत्ति कार्यक्रम (स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन) स्नातक आयुर्वेद छात्रों के बीच शोध में रुचि और योग्यता को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम छात्रों को आयुर्वेद में अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अल्पकालिक स्वतंत्र परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच, 'स्पार्क' कार्यक्रम के माध्यम से 289 आयुर्वेद कॉलेजों ने लाभ उठाया।

आयुर्वेद अनुसंधान का एआई-अनुवाद

- वैज्ञानिक जानकारी को सभी तक पहुँचाने के लिए, सीसीआरएएस ने मार्च 2026 में 'अनुवादिनी एआई' के साथ साझेदारी की—जो शिक्षा मंत्रालय के एआईसीटीई द्वारा विकसित एक कृत्रिम मेधा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। इस सहयोग के माध्यम से, सीसीआरएएस अपने व्यापक शोध परिणामों, शैक्षिक संसाधनों और त्रैमासिक चिकित्सा पत्रिकाओं का 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहा है।
- भाषा की बाधाओं को तोड़कर, यह पहल आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान तक पहुँच को आसान बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरे भारत में छात्र, चिकित्सक और आम लोग इन वैज्ञानिक जानकारियों को आसानी से पढ़ और समझ सकें।

आयुर्वेद आहार

- इन सुरक्षा सिद्धांतों को औषधियों से आगे पोषण के क्षेत्र तक विस्तारित करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद आहार के लिए एक मानकीकृत विनियमन लागू किया है। यह पहल प्रामाणिक शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर प्रामाणिक आयुर्वेदिक आहार उत्पादों की एक सूची तैयार करती है। यह सूची पारंपरिक खाद्य निर्माताओं के लाइसेंस और पंजीकरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पारंपरिक खाद्य निर्माताओं के लिए एक पारदर्शी और विनियमित क्षेत्र बनाती है, जिससे भारत और दुनिया भर में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है।

आयुष क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 का आवंटन

- केंद्रीय बजट (2026-27) में आयुष मंत्रालय के लिए 4,408 करोड़ रुपये का आवंटन देशभर में आयुष स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने और आयुष से जुडी अन्य अवसंरचना व वैश्विक पहुंच को मज़बूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। बजट में कई प्रमुख पहलों की घोषणा की गई:
- शिक्षा, नैदानिक सेवाओं और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों (एआईआईए) की स्थापना।
- गुणवत्ता, मानकीकरण और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन।
- पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और वैश्विक स्तर पर पहुँच को बढ़ावा देने के लिए जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Practice Question)

- **प्रश्न: राष्ट्रीय आयुष मिशन (National Ayush Mission - NAM) और भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका उद्देश्य देश में आयुष सेवाओं का विस्तार और एकीकरण करना है।
2. इसके तहत प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाओं का सह-स्थान (co-location) किया जा रहा है।
3. भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 23 सितंबर को 'आयुर्वेद दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains Practice Question)

- **प्रश्न:** *"पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक साक्ष्य-आधारित (evidence-based) अनुसंधान के साथ जोड़ना भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और गैर-संचारी रोगों (NCDs) के प्रबंधन के लिए आवश्यक है।"*
- राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में, भारत में एकीकृत चिकित्सा (Integrative Medicine) मॉडल को लागू करने के लाभों और इससे जुड़े अनुसंधान व मानकीकरण की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। **(10 अंक / 150 शब्द)**

Result Mitra

Towards recognising women farmers

Maharashtra's passage of the Women Farmers' Empowerment Bill, granting women independent recognition as farmers irrespective of land ownership, brings into focus the structural bias against the female agricultural workforce, highlights the need for a database of women farmers and using it to ensure access to welfare schemes

ECONOMIC NOTES

Sanchit Gupta
Tanu M. Goyal

Picture a farmer. The image that comes to mind is of a man. But when one looks at who is actually farming, she is increasingly likely to be a woman. This perception-reality mismatch is caused by age-old practices of collecting data, designing policies and defining who a farmer is. It makes millions of women who work on farms, make agricultural decisions and contribute to production nearly invisible. That may, however, finally be beginning to change.

In July 2026, Maharashtra passed the Women Farmers' Empowerment Bill, granting women independent recognition as farmers irrespective of land ownership, through a Woman Farmer Certificate. This is the first Indian State legislation to give enforceable legal form to the activity-based, land-delinked definition of 'farmer' that the National Policy for Farmers set out in 2007 but never operationalised. The Bill arrives nearly two decades after that policy, and 15 years after a comparable law was first proposed at the national level (a lapsed bill introduced in the Rajya Sabha in 2011). It is, in effect, the culmination of three decades of women farmers' movements backed by civil society organisations.

State-level efforts have also sought to recognise women farmers before this. Kerala's Kudumbashree collectives have enabled women to participate in group farming, while Odisha's KALIA scheme has reached landless and sharecropper women. But a women farmers' registry delinked from land records had been missing. Maharashtra's legislation, therefore, represents a potentially important shift, from recognising the owner of agricultural land to recognising the person who actually farms. This matters because women's participation in agriculture has risen sharply.

The recognition gap

In 2025, agriculture employed roughly 110 million women and 127 million men (rural, as per the PLFS, Census adjusted), bringing the sector close to gender parity. Women's agricultural workforce has more than doubled since 2017-18, and nearly three-quarters of all rural women workers are now in agriculture, compared with less than half of men. Regrettably most women work without pay. In 2025, more than 40% of female agricultural workers were unpaid, against 20% of men (**Chart 1**). By contrast, nearly 63% of men were own-account workers compared with 39% of women. While women's position has improved over time, the gap remains stark. This is where the question of recognition becomes critical, as women are increasingly farming but are not necessarily recognised as farmers.

The worker-owner dichotomy

In India, women largely work on the family lands, even though they may not own it or have their name on the land records, as patriarchal norms have meant that the land records are primarily in men's names. Subsequently, only 14% of operational agricultural land holdings (as measured primarily through land records) are with women (according to the Agricultural Census 2015-16). The person whose name is in the records gets included in the database and receives the benefits. As a result, not only does the recognition of women agricultural workers as farmers remain ambiguous, but they are also unable to access key Central and State agricultural schemes and incentives linked to land titles (land records).

All States have a large population of women engaged in farming who are never counted as farmers. Since each State uses its land revenue records as the source of truth for administrative purposes, the structural bias against women is carried forward into scheme access and databases. This ultimately translates into women farmers being unable to access credit, subsidies, technology, extension services and other related opportunities. For instance, only 23% of women have been beneficiaries of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme, which provides direct financial assistance of ₹6,000 per year to eligible landholding farmer families to support their agricultural expenses and household needs. For some States, the gap widens (**See Chart 2**).

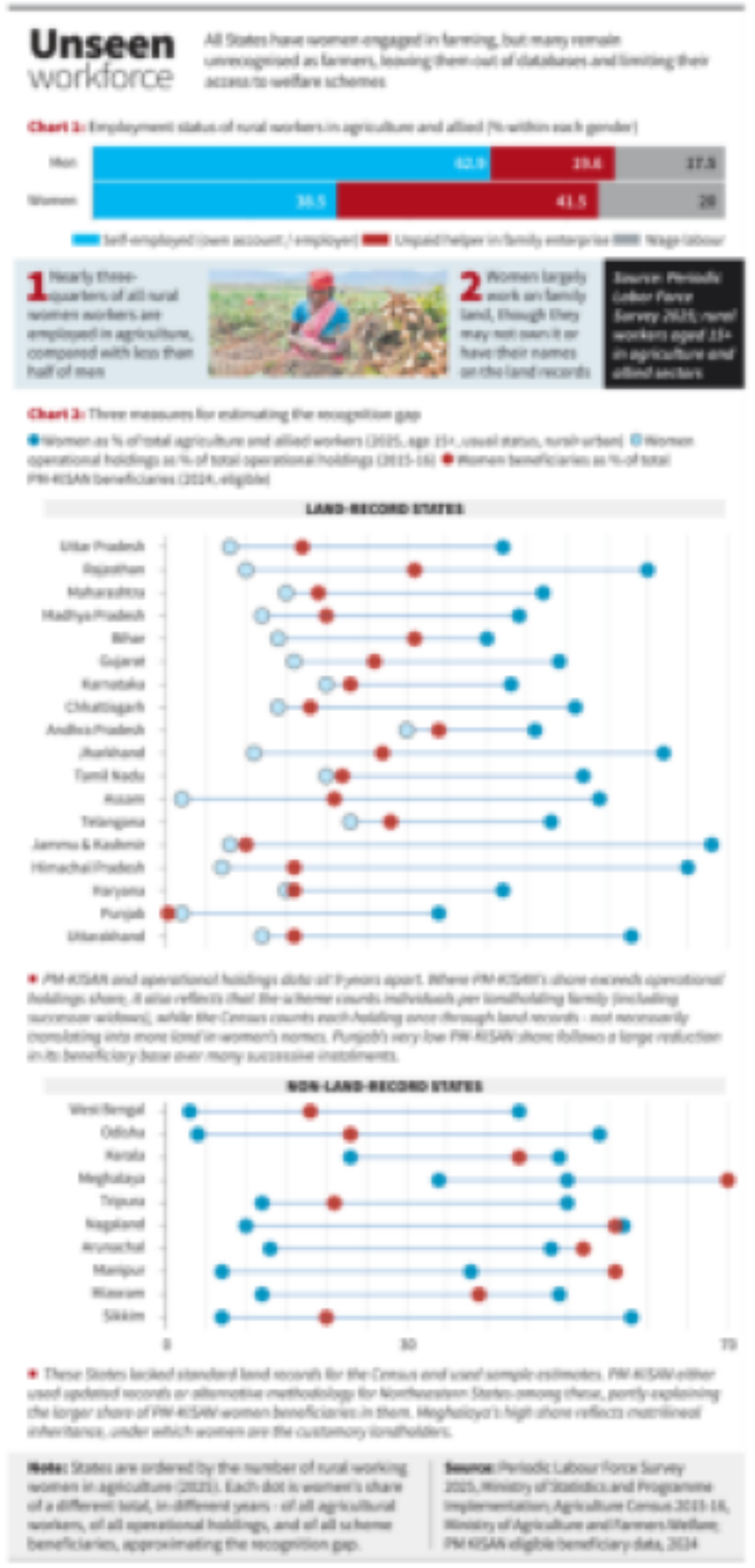

The Maharashtra Act recognises women engaged in agriculture for at least one agricultural season a year, irrespective of the nature of the land

Even in States where the share of women in the agriculture workforce is more than 50%, the share of women beneficiaries in most States is less than one-third. The exceptions are revealing. Meghalaya, where women account for 70% of beneficiaries, followed by Kerala with 44% stand apart. These States have institutional or social arrangements that provide women with greater recognition or access to land and agricultural resources. In some northeastern States, customary tenure and matrilineal systems matter; in Kerala, collective farming through groups such as Kudumbashree provides an alternative route to participation and recognition.

At the other extreme are States with some of the widest gaps. In Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh, women make up nearly two-thirds of the workforce but represent a small fraction of beneficiaries. The binding constraint, therefore, is not land itself but the identification system built on it. Where the land record is the gatekeeper, women are more likely to be filtered out; where an alternative mechanism exists, women's access rises substantially.

Year of the Woman Farmer

While the Maharashtra legislation came after decades of advocacy, it is well timed. With the United Nations naming 2026 the International Year of the Woman Farmer, Maharashtra has taken a potentially transformative first step and paved the way for other States. The Maharashtra Act broadens the definitions of 'agriculture' and 'farmer' to recognise women residents engaged in agriculture for at least one agricultural season a year, irrespective of the nature of the land, through a 'Woman Farmer Certificate'.

Importantly, it explicitly recognises categories like landless cultivator, landless livestock rearer, agricultural labourer, plantation labourer, and pastoralist. In principle, this creates a route through which women who do not own land can obtain an independent agricultural identity and gain access to state welfare schemes and credit. But recognition on paper is only the beginning. Implementation will require either self-registration or identification of women farmers by the Gram Sabha, including women who have no land or no land titles in their name. In both cases, this will require a robust information campaign.

This also provides for a new database of women farmers. Connecting this database with existing agricultural databases and avoiding duplication or exclusion will need to be worked out, presenting an opportunity for States to work together. A standardised system across States, for establishing common definitions for identifying women farmers, issuing certificates, and maintaining databases, would make it easier to link the identities of women farmers across schemes and administrative platforms, while avoiding multiple registrations.

But recognition must then translate into access. Linking these certificates to the Agri Stack (a digital platform developed by the Union Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) and issuing FarmerIDs to the women is essential to integrating them into the broader digital agricultural ecosystem. However, for recognition to translate into empowerment, continuous efforts at the local level will be needed to make women farmers aware of the schemes and effectively ensure their access.

(The authors work at the Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER). Views expressed are personal.)

THE GIST

In July 2026, Maharashtra passed the Women Farmers' Empowerment Bill. This is the first Indian State legislation to give enforceable legal form to the activity-based, land-delinked definition of 'farmer'

It explicitly recognises categories such as landless cultivators, landless livestock rearers, agricultural labourers, plantation labourers and pastoralists. In principle, this creates a route through which women who do not own land can obtain an independent agricultural identity and gain access to welfare schemes

But recognition must then translate into access. Linking these certificates to Agri Stack and issuing Farmer IDs to women is essential to integrating them into the broader digital agricultural ecosystem

Economy – कृषि
Social Justice – महिला
Indian Society – महिला
महिला [illegible]

"Towards recognising women farmers" (महिला किसानों को मान्यता)

- **1. मुख्य पृष्ठभूमि (Background)**
- **महाराष्ट्र का नया विधेयक:** महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने भूमि के स्वामित्व (land ownership) से अलग हटकर, कृषि गतिविधियों के आधार पर महिलाओं को 'किसान' के रूप में कानूनी मान्यता दी है।
- **महिला किसान प्रमाण पत्र (Woman Farmer Certificate):** इसके तहत उन महिलाओं को भी किसान का दर्जा दिया जाएगा जो भूमि की मालिक नहीं हैं, जैसे—भूमिहीन खेतीहर, पशुपालक, बटाईदार (sharecroppers) और कृषि मजदूर।

2. कृषि में महिलाओं का योगदान और पहचान का संकट (The Recognition Gap)

- **दृश्यता की कमी:** कृषि क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं का लगभग तीन-चौथाई (nearly 3/4th) हिस्सा जुड़ा हुआ है।
- **अवैतनिक श्रम (Unpaid Labor):** लेख के अनुसार (Chart 1), वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में **41% से अधिक महिलाएँ unpaid helper (बिना वेतन के काम करने वाली पारिवारिक सहायक)** के रूप में काम कर रही थीं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा केवल 20% था।
- **भूमि स्वामित्व में कमी:** भारत में केवल **14% कृषि जोत (landholdings)** महिलाओं के नाम पर हैं। भूमि रिकॉर्ड में नाम न होने के कारण उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, क्रेडिट (ऋण), सब्सिडी और बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है।

3. सरकारी योजनाओं में अंतर (Schemes & Disparity)

- **PM-KISAN का उदाहरण:** पीएम-किसान योजना के तहत केवल **23% महिलाएँ** ही लाभार्थी हैं, क्योंकि यह योजना भूमि स्वामित्व (land title) से जुड़ी हुई है।
- **राज्यों की स्थिति (Chart 2):** केरल (जहाँ कुदुम्बश्री/Kudumbashree मॉडल है) और मेघालय (जहाँ मातृसत्तात्मक व्यवस्था है) जैसे राज्यों में महिलाओं को कृषि संसाधनों तक बेहतर पहुँच प्राप्त है। वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कार्यबल में महिलाओं की संख्या अधिक होने के बावजूद सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में उनका हिस्सा कम है।

4. आगे की राह और सुझाव (Way Forward)

- **वर्ष 2026:** संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष **2026 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' (International Year of the Woman Farmer)** के रूप में घोषित किया है।
- **डेटाबेस और एग्री स्टैक (Agri Stack):** इन प्रमाण पत्रों को केंद्र सरकार के 'एग्री स्टैक' (डिजिटल प्लेटफॉर्म) से जोड़ा जाना चाहिए ताकि महिलाओं को पहचान पत्र (Farmer ID) आसानी से मिल सके।
- **ग्राम सभा की भूमिका:** ज़मीनी स्तर पर महिला किसानों की पहचान और पंजीकरण के लिए ग्राम सभाओं और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Practice Question)

प्रश्न: कृषि क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति और हालिया नीतिगत पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महाराष्ट्र, भूमि स्वामित्व से इतर कृषि गतिविधियों के आधार पर महिलाओं को 'किसान' के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
2. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2026 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' (International Year of the Woman Farmer) के रूप में घोषित किया है।
3. 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) के अनुसार, भारत में कृषि में कार्यरत अधिकांश महिलाएँ बिना वेतन वाले पारिवारिक सहायक (Unpaid Helper) के रूप में कार्य करती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains Practice Question)

- **प्रश्न:** *"भारतीय कृषि का 'स्त्रीकरण' (Feminisation of Agriculture) तेज़ी से हो रहा है, किंतु भूमि स्वामित्व के अभाव और नीतिगत पहचान की कमी के कारण महिला किसानों को संस्थागत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता।"* इस कथन के आलोक में महिला किसानों के समक्ष मौजूद संरचनात्मक बाधाओं की पहचान कीजिए तथा महाराष्ट्र द्वारा हाल ही में पारित 'महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक' जैसे उपायों की प्रभावशीलता की विवेचना कीजिए। **(15 अंक / 250 शब्द)**

महत्वपूर्ण तथ्य

YouTube Homework

- 301

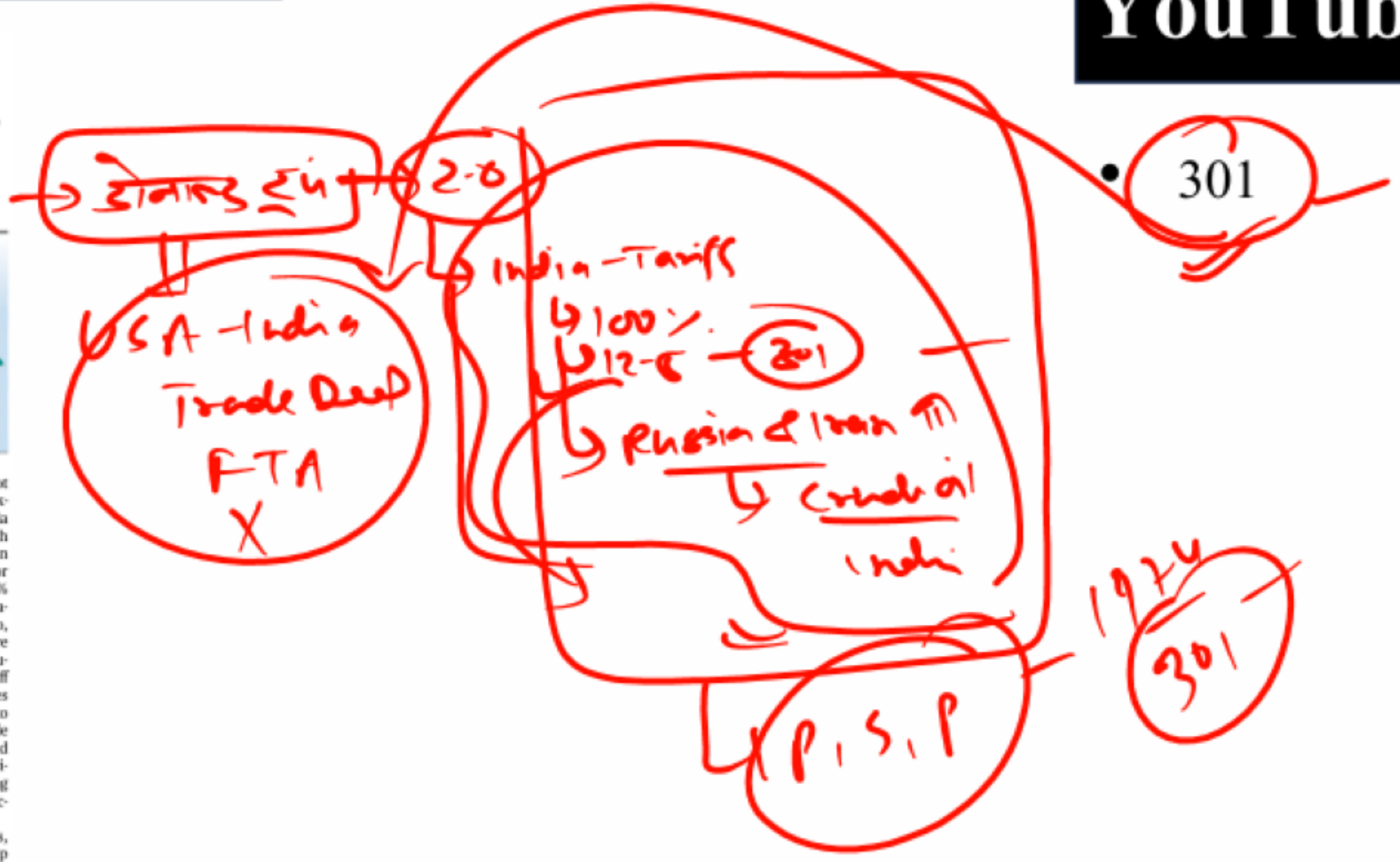

Trade deal unlikely till U.S. probes India's competitors also over excess capacity

Sriram Lakshman
WASHINGTON DC

India and the U.S. are unlikely to sign a trade deal until the United States launches a series of fresh 'Section 301 investigations', concludes them, and places tariffs on India's competitors such as Pakistan, Sri Lanka, and the Philippines, a person familiar with the process has said.

It was a "strategic mistake", according to the person, that Pakistan was not included in the list of countries investigated in the 'excess capacity' 301 investigations opened in March 2026.

An announcement of fresh 301 investigations against some of India's competitor countries is likely in the near future, *The Hindu* has learned, although the timelines and the subject matters for these 301s have not yet been decided.

For this reason, it is highly unlikely that a trade deal will be concluded around Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal's upcoming visit to the North American country for the G-20 trade ministerial that starts on September 30.

These developments appear to be consistent with Commerce Secretary Rajesh Agrawal's remarks at the Global Fintech Fest 2026 earlier this month. Mr. Agrawal had said that India operates largely on an MFN (Most Favoured Nation) tariff basis, while the U.S. operates on an executive tariff basis, and that a trade agreement would require an architecture with differentials and preferential market access structure for India.

The '301s' are part of how the U.S. government is working around the February 2026 U.S. Supreme Court ruling that President Donald Trump's 'reciprocal' tariffs were an unlawful application of the International Emergency Economic Powers Act. Prior to this ruling, India and the U.S. had arrived at an Interim Agreement on trade that was announced via an India-U.S. joint statement issued on February 6.

The general tariff rate for Indian goods entering the U.S. under the interim deal was going to be 18%, giving India an advantage over its main competitors. These include not just Pakistan (19%), which is the most politically sensitive country in New Delhi's calculus, but also Vietnam (20%), Sri Lanka (20%), Bangladesh (19%) and the Philippines (19%). Following the scrapping of these tariffs, they trade with the U.S. on an MFN basis.

Central challenge

A central challenge to concluding the India-U.S. deal is that Pakistan, Sri Lanka and the Philippines were subject to 301 probes for forced labour, but are not on the 301 probe list for excess capacity, which India was subject to. Both probes were launched in March 2026. Pakistan, for instance, is tariffed at 10% as a result of the forced labour 301 investigation. So, at the moment, there are no similar legal instruments through which tariff rates on these countries could be raised further to their previous levels, while India is likely to be tariffed at 8% in the excess capacity investigation, bringing the overall tariff rate it faces back up to 18%.

To complicate matters, last Friday, Mr. Trump signed the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act into law, enabling the U.S. government to impose up to 100% tariffs on the top five importers of Russian oil. This includes India and China.

New Delhi is the second-biggest market for Russian crude oil.

There is reporting to suggest that the bill, which was originally scheduled for consideration after the midterm elections, was rushed through in time for the September 24 meeting between Chinese President Xi Jinping and Mr. Trump in Washington, DC.

Uneven markets

The United States government uses 'Section 301' as an alternative to the 'reciprocal tariffs.'

- India, Pakistan, and Sri Lanka were subject to probes for 'forced labour', but only India is on the probe list for 'excess capacity'
- India is likely to face **8%** tariff in the 'excess capacity' investigation to bring the overall tariff rate it faces up to **18%**

महत्वपूर्ण तथ्य

Karnataka Houses adopt resolution against report on Western Ghats

The Hindu Bureau
BENGALURU

The Karnataka Legislative Assembly and the Council on Tuesday adopted an unanimous resolution urging the Union government to confine the Ecological Sensitive Area (ESA) identified as per the Kasturirangan report on conservation of Western Ghats to only the notified forests.

It sought a year's time for the State to help take up a physical survey of the areas coming under ESA.

"The draft notification issued by the Centre regarding the ESA in Karnataka should not be finalised till the next one year, when the physical survey would be completed. The final decision on ESA should be taken only after the State submits its report to the Centre and only after detailed discussion by the Centre with the State," said the resolution.

The resolution said that Karnataka would constitute a high-level committee to suggest measures to correct the "lacunae" in the report through appropriate modifications.

The Centre, on July 27, issued the seventh draft notification on ESA based on the report, which comprises 20,668 sq. km of areas spread over 1,449 villages across 10 districts. The State's stand on ESA would mean reducing it to about 16,000 sq. km.

The resolution alleged that the ESA was not accurate as it had been determined based on satellite data instead of a joint physical survey by the Forest and Revenue departments.

YouTube Homework

Gadgil Report

महत्वपूर्ण तथ्य

कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट (Kasturiranjan Report)

पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट (2013)

- भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने डॉ. के. कस्तूरीरंगन (पूर्व ISRO प्रमुख) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल (HLWG) का गठन किया था। इसका उद्देश्य गाडगिल समिति (Gadgil Commission) की सिफारिशों का पुनर्मूल्यांकन करना और पर्यावरण संरक्षण व विकास के बीच संतुलन बनाना था।

प्रमुख सिफारिशें और बिंदु:

- **37% क्षेत्र का संरक्षण:** समिति ने पूरे पश्चिमी घाट (लगभग 60,000 वर्ग किमी क्षेत्र) के **37% भाग** को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area - ESA) घोषित करने की सिफारिश की।
- **गतिविधियों पर प्रतिबंध:** ESA घोषित क्षेत्रों में निम्नलिखित पर पूरी तरह रोक लगाने का सुझाव दिया गया:
  - खनन (Mining) और खदान कार्य।
  - थर्मल पावर प्लांट।
  - प्रदूषण फैलाने वाले भारी उद्योग (Red Category Industries)।
  - 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के बड़े भवन और निर्माण परियोजनाएं।

विकास की अनुमति: गाडगिल रिपोर्ट की तुलना में कस्तूरीरंगन रिपोर्ट अधिक व्यावहारिक मानी गई, क्योंकि इसने सतत विकास (Sustainable Development) को ध्यान में रखते हुए सीमित कृषि, जलविद्युत परियोजनाओं (शर्तों के साथ) और बुनियादी ढांचे के निर्माण की अनुमति दी।

स्थानीय विरोध: केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस रिपोर्ट का भारी विरोध हुआ, क्योंकि स्थानीय लोगों और सरकारों को डर था कि इससे कृषि, बगान (Plantations) और लोगों के पुनर्वास पर असर पड़ेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

Officials flag concerns over tourists destroying Neelakurinji blooms

Sandeep Vellaram
IDUKKI

The rampant destruction of Neelakurinji blooms in unprotected areas by tourists poses a serious threat to the biodiversity of Munnar in Keralam.

According to Forest department officials, Neelakurinji has bloomed this year across Chinnakkanal, Lakshmi, Pallivasal, and nearby hills. Regulated visitor entry was granted at Chokramudy hills near Devikulam by the Forest department, while the Kanan Devan Hills Plantations permitted access to Korandakkad near Mattupetty, with both authorities safeguarding the plants within these designated zones.

Under threat: Neelakurinji in bloom on the Chokramudy hills near Devikulam in Idukki district of Kerala. SPECIAL ARRANGEMENT

However, officials noted that travel vloggers have been pinpointing unprotected locations and posting footage on social media. Influenced by these videos, large groups of tourists have been trekking through unregulated hills, trampling blooms, and uprooting plants.

Munnar Divisional Forest Officer (DFO) Abhay Yadav noted that despite enforcement efforts, the destruction and uprooting of the rare species continue across the hills.

Senthil Kumar. M., CEO of Kestrel Adventures and organiser of the Munnar Marathon, stated that nearly 500 tourists trekked Lakshmi Hills during the early hours of last Sunday to view the blooms.

"Some visitors trampled the plants, danced among the flowers, and even slept in the shrubs to capture photos and videos for Instagram," said Mr. Kumar.

He warned that unchecked access to unrestricted areas could wipe out the local Neelakurinji population entirely.

महत्वपूर्ण तथ्य

- **नीलाकुरिंजी (Neelakurinji)** एक अत्यंत दुर्लभ और अनूठा फूल है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के **पश्चिमी घाट (Western Ghats)** में पाया जाता है।
- इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं:

1. मुख्य विशेषताएँ

- **वैज्ञानिक नाम:** इसका वनस्पति नाम *Strobilanthes\ kunthiana* है।
- **12 साल का चक्र:** यह पौधा **हर 12 साल में केवल एक बार** ही खिलता है।
- **'नीलगिरी' नाम की वजह:** जब यह फूल खिलता है, तो पूरी पहाड़ियाँ नीले-बैंगनी रंग की चादर से ढक जाती हैं। इसी कारण इन पहाड़ियों को **'नीलगिरी' (Blue Mountains)** नाम मिला।
- **आवास (Habitat):** यह पश्चिमी घाट के **शोला वनों (Shola Forests)** और 1300 से 2400 मीटर की ऊँचाई वाले घास के मैदानों (Grasslands) में पाया जाता है। केरल का **इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (Eravikulam National Park)** इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है।

2. पर्यावरण और सांस्कृतिक महत्त्व

- **पलियन जनजाति (Paliyan Tribe):** तमिलनाडु की यह पारंपरिक जनजाति नीलाकुरिंजी के खिलने के 12-वर्षीय चक्र का उपयोग अपनी आयु की गणना करने के लिए करती थी।
- **संरक्षण की स्थिति (Conservation Status):** यह एक अति-संवेदनशील (Endangered) प्रजाति है जो केवल विशिष्ट जलवायु स्थिति में ही पनपती है।
- **खतरे:** चाय/कॉफ़ी के बागानों के विस्तार, पर्यटन के दबाव और अवैध निर्माण के कारण इसके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुँच रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Internal Security

31 Dec 2029

Drug trade to be uprooted from India by 2029 end: Shah

The Union Home Minister says enforcement agencies must break trafficking chains through financial investigations, tracing digital links, and targeting the profits generated by drug cartels

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Union Home Minister Amit Shah on Tuesday set a target of December 31, 2029 to "uproot" drug trade from the country.

"For the past five years, we have been taking one step after another in an effort to achieve the difficult goal of a drug-free India...the time has now come to deliver a decisive blow against narcotics, which have become the most serious threat to the country and the world, and to achieve victory through collective efforts. By 31 December 2029, we will collectively succeed in uprooting the drug trade from India," Mr. Shah said.

The Minister said the country's anti-narcotics strategy should shift from merely seizing drugs to dismantling the networks behind the trade. He directed agencies to launch a campaign to deport foreign nationals involved in drug trafficking and bar them

Home Minister Amit Shah inaugurates the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force in New Delhi on Tuesday. ANI

from re-entering India. Fugitive traffickers operating from abroad should also be apprehended and brought before Indian courts, he said.

Addressing the third National Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Force (ANTF) of States and Union Territories in Delhi, Mr. Shah said enforcement agencies must focus on breaking entire trafficking chains through financial investigations, tracing digital links, and targeting the profits generated by drug cartels.

"Instead of maintaining a seizure-centric approach, we must move forward with the objective of dismantling entire networks," he said, adding, cartels should be attacked at three levels: the entry point, the inter-State distribution system, and local sales networks within districts. To sharpen enforcement, districts will be classified into three categories: those where drugs are manufactured or enter the country, those that function as transportation corridors, and those where drug consumption takes place.

Mr. Shah also called for greater use of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and stressed on the need for a comprehensive road map from investigation to conviction in coordination with public prosecutors.

The Minister said all loopholes along borders and drug production centres must be plugged and asked ANTFs to make the conversion of information into actionable intelligence an integral part of policing culture in their respective States.

Mr. Shah said the conference marked a transition "from meeting to mission, from reporting to results, from seizure to dismantling networks, and from case to conviction".

The two-day conference, organised by the Narcotics Control Bureau (NCB), is being attended by ANTF heads from 36 States and Union Territories.

YouTube Homework

- Golden Crescent
- Golden Triangle

- 3rd National Conference of Anti Narcotics Task Force

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत सरकार ने देश में नशे की समस्या को समाप्त करने और युवाओं को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्य पहलों की जानकारी निम्नलिखित है:

1. नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने **15 अगस्त 2020** को इस अभियान की शुरुआत की थी।
- **केंद्रित दृष्टिकोण:** यह अभियान देश के सबसे अधिक प्रभावित जिलों (शुरुआत में 272 जिले, अब सभी जिलों) में लागू किया गया है।
- **युवा और महिला भागीदारी:** इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को बड़े पैमाने पर जोड़ा गया है।
- **डिजिटल पहल:** अभियान की गतिविधियों को ट्रैक करने और लोगों तक पहुँच बनाने के लिए 'NMBA मोबाइल ऐप' और पोर्टल लॉन्च किया गया।

2. संस्थागत और कानूनी ढाँचा (Institutional & Legal Steps)

- **NCORD (नार्को समन्वय केंद्र):** राज्य और केंद्रीय एजेंसियों (जैसे NCB, पुलिस, राजस्व विभाग) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए चार स्तरीय (राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला और उप-मंडल) NCORD व्यवस्था बनाई गई है।
- **NDPS एक्ट की सख्ती:** नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए 'नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (NDPS) अधिनियम' को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
- **निदान (SIMS/NIDAAN) पोर्टल:** नशीले पदार्थों के तस्करों और अपराधों का डेटाबेस तैयार करने के लिए **'निदान' (NIDAAN)** पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे तस्करों पर नज़र रखी जा सके।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. उपचार और पुनर्वास (Treatment & Rehabilitation)

- **राष्ट्रीय मादक द्रव्य मांग कटौती कार्य योजना (NAPDDR):** इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके नशामुक्ति केंद्रों और पुनर्वास केंद्रों का संचालन किया जाता है।
- **ATF (Addiction Treatment Facilities):** AIIMS दिल्ली के सहयोग से देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त इलाज के लिए 'एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज' की स्थापना की जा रही है।
- **हेल्पलाइन नंबर:** नशामुक्ति से जुड़ी सलाह और सहायता के लिए टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर **14446** शुरू किया गया है।

4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- भारत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए **UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)** और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर सीमा सुरक्षा एजेंसियों के ज़रिए सख्त निगरानी रखता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

India's vast canal network offers a land-free path to solar power

Similar to floating solar, the biggest advantage of canal-top photovoltaics is that they require virtually no additional land, especially as land acquisition for large-scale solar is also becoming increasingly expensive; in Punjab, the installation of 20 MW of canal-top systems is estimated to have saved nearly 100 acres of land

Shantanu Roy

As India expands its clean energy capacity, finding land for solar projects is becoming a challenge. This is driving interest in innovative solar solutions that can generate power without needing more land.

The recently approved PM Surya Sarovar Yojana (PM-SSY) is a step in this direction, aiming at developing 5,000 MW of floating solar capacity on reservoirs and other inland water bodies across the country.

However, India's water infrastructure has more to offer: the country's vast canal network – one of the largest in the world – is another under explored avenue to generate solar power. Built over existing irrigation and water-supply canals, canal-top photovoltaics (CTPV) provides a unique approach to turn them into clean energy assets.

In CTPV, solar panels are mounted on specialised structures built over canal stretches. Unlike floating solar systems, where panels are installed on floating platforms on water bodies, CTPV systems use elevated structures above the canals.

Systems can be built based on the canal's width, design, and orientation. The elevated structures may span the canal or can be installed along the canal banks. In all cases, the design must allow unobstructed water flow.

Advantages of CTPV

Similar to floating solar, the biggest advantage of CTPV is that it requires virtually no additional land. With land acquisition for large-scale solar becoming increasingly challenging and expensive, CTPV offers a promising way by using India's canal infrastructure. For instance, in Punjab, the installation of 20 MW of CTPV systems is estimated to have saved nearly 100 acres of land.

CTPV offers another advantage. With solar panels covering canal stretches, the amount of water lost to evaporation can be reduced. This can be particularly useful in India's water-stressed regions. The cooling effect of the water beneath the panels could improve panel performance in hot weather. A 1-MW CTPV system over the Narmada Canal in Mehsana, Gujarat, commissioned in 2012, reportedly saves close to 9 million litres of water every year while generating 1.6 million units of electricity annually.

While CTPV remains largely a niche application, India has been an early adopter, with its first installation in Mehsana in 2012. Between 2014 and 2017, two 10-MW CTPV systems were commissioned in Vadodara, Gujarat, and 20 MW of CTPV systems were commissioned in Punjab between 2017 and 2018.

Solar panels seen installed above the Narmada canal in Chandrasan village, Gujarat, in 2012. The State hosted India's first canal-top photovoltaics. AP

In September 2025, the Punjab Energy Development Agency invited 'expressions of interest' for 40-MW CTPV projects across Punjab's canal network, spanning over 10,000 km. Haryana has also initiated efforts to explore CTPV systems over six of its irrigation canals.

CTPV also received policy support in 2014, when the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) launched a pilot-cum-demonstration scheme for grid-connected CTPV and canal bank projects with a target of 50 MW each for CTPV and canal-bank projects. The scheme also included financial assistance of Rs 3 crore and Rs 1.5 crore per MW or 30% of project cost, whichever was lower, for CTPV and canal bank systems, respectively.

An assessment in 2024 (co-authored by CSTEP, where the author works) estimated India's CTPV and canal bank potential at around 131 GW (for canals up to 30 m wide and vertical bifacial installations for canals over 30 m wide). Considerations such as solar irradiation, canal characteristics, distance from substations, and protected areas were included in the assessment to identify the best-suited canal stretches across India. The five States with the highest potential were Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Andhra Pradesh, and Punjab.

Potential roadblocks

Despite India's early progress, deployment has remained limited for more than a decade after the first installation.

High system cost is the primary bottleneck. CTPV systems are more expensive than ground-mounted ones as they require elevated structures to span canal stretches. These structures need to be designed to not disrupt canal operations and be sturdy enough to withstand winds. They also need additional structural steel, foundations, and access provisions for operations and maintenance, all of which add to the overall costs.

Maintenance tasks, including cleaning panels and replacement and repair work, can also prove difficult when the structures are elevated above a working canal.

The linear nature of CTPV systems, which run along the course of canals, can also pose challenges when canals follow irregular paths or change direction. This can increase the cost of producing electricity, especially when electrical substations or transformers are not strategically located.

Renewed policy approach

PM-SSY is expected to revitalise the floating solar segment and drive its adoption across India, signalling growing policy interest in exploring land-neutral solar applications. This focus could extend to other solutions like CTPV, potentially giving the technology greater policy attention and momentum.

However, to overcome the aforementioned structural challenges and scale CTPV deployment, identifying and prioritising suitable canal stretches will be critical. Factors such as land scarcity, nearby electricity demand and grid connectivity, and canal orientation and geometry should be considered while selecting sites to maximise the economic viability of CTPV systems.

CTPV also requires accessible and tailored financing mechanisms, including viability gap funding and low-cost debt, to make it an attractive option for developers. This will help support early projects, allowing developers to build experience and eventually reducing costs through scale and standardisation.

However, the 2014 MNRE scheme on CTPV shows that financial support alone may not suffice to convert pilots into large-scale deployment.

A renewed policy approach that includes financial assistance and standardised specifications and guidelines, capacity building of state nodal agencies, irrigation departments, and other concerned agencies, and streamlined process flows is required.

While CTPV may not fully substitute ground-mounted or rooftop solar, they offer an untapped opportunity for India's renewable energy expansion. Even if a fraction of CTPV's technical potential is realised, it could significantly boost India's renewable energy capacity without adding to the pressure on land resources.

(Shantanu Roy is the Sector Coordinator for Renewables and Energy Conservation at the Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), a research-based think tank. shantanu@cstep.in)

THE GIST

- In CTPV, solar panels are mounted on specialised structures built over canal stretches
- Systems can be built based on the canal's width, design, and orientation and elevated structures may span the canal or can be installed along the canal banks
- With solar panels covering canal stretches, the amount of water lost to evaporation can be reduced, which can be particularly useful in India's water-stressed regions

YouTube Homework

- PM-KUSUM

महत्वपूर्ण तथ्य

- **प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana - PM-SSY)**

1. यह योजना कब शुरू हुई?

- **मंजूरी तिथि:** केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) द्वारा इस योजना को **31 जुलाई 2026** को मंजूरी दी गई।
- **कार्यान्वयन की अवधि:** इसे वित्त वर्ष **2026-27 से 2030-31** की अवधि के लिए लागू किया गया है।
- **कुल वित्तीय परिव्यय (Budgetary Outlay): ₹5,070 करोड़।**

2. कौन-सा मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसी है? (नोडल एजेंसी)

- **मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** (Ministry of New and Renewable Energy - MNRE)।
- **कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency): भारतीय सौर ऊर्जा निगम** (Solar Energy Corporation of India - SECI)।
- **योजना का स्वरूप:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)** है।

3. योजना का मुख्य उद्देश्य (Objectives)

- **फ्लोटिंग सोलर क्षमता बढ़ाना:** देश के जलाशय, बांध, झीलें और औद्योगिक जल निकायों पर **5,000 मेगावाट (5 GW)** क्षमता की फ्लोटिंग सोलर (Floating Solar) परियोजनाएँ स्थापित करना।
- **भूमि अधिग्रहण की समस्या से मुक्ति (Land-Neutral Solution):** कृषि योग्य या वनीय भूमि का अधिग्रहण किए बिना जल निकायों की खाली सतह का कुशल उपयोग करना।
- **ऊर्जा भंडारण (Energy Storage) को बढ़ावा देना:** ग्रिड स्थिरता और पीक आवर्स (Peak hours) की माँग को पूरा करने के लिए कम से कम 2 घंटे का **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)** जोड़ना।
- **जल संरक्षण:** जल निकायों की सतह पर सौर पैनल लगाने से पानी के वाष्पीकरण (Evaporation) में कमी लाना।
- **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** प्रतिवर्ष लगभग **10 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन** को कम करना और भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना।

महत्वपूर्ण तथ्य

Freezing democracy

The ECI is functioning as a tool of the Bharatiya Janata Party in West Bengal

Almost 28 years after Mamata Banerjee set up the All India Trinamool Congress and designed its symbol of 'grass and flowers', the Election Commission of India (ECI) on September 17, 2026, froze the party's name and symbol. The 14-page order stated that since two rival groups – one led by Ms. Banerjee and the other by Arup Roy – are now claiming to be the party, the matter requires "substantive determination", and neither group can use the party's name or symbol. The ECI has allotted new names and symbols to both groups. The ECI's move has effectively denied Ms. Banerjee of her party's name and symbol. For nearly three decades, crores of voters have placed their faith in the party's name and symbol, elected Ms. Banerjee as Chief Minister of West Bengal three times, and sent scores as its MPs to Parliament. Even in the April 2026 West Bengal Assembly polls, 41% of the electorate, or more than 2.60 crore voters, voted for Ms. Banerjee's party, while the margin between it and the Bharatiya Janata Party was only about 32 lakh votes. Opposition parties, including the Congress, have said that similar attempts to freeze the name and symbol were made in the case of the Shiv Sena, calling such action of freezing the name and the symbol as "party theft" and a case of democratic decline.

Political parties are organic entities that keep democracy vibrant and alive and any attempts to engineer their dissolution is an attack on the very foundations of India's democracy. If a political party has to wither away, it should happen only through the determination of the people. Serious questions have been raised about the role of the ECI, which held the West Bengal Assembly polls in 2026 after a hurriedly organised Special Intensive Revision (SIR) of the electoral rolls that left lakhs of voters out, and is now freezing the name and symbol of the principal Opposition party. Free and fair elections form the bedrock of the republic. When political parties, which are engines for ensuring that the will of the electorate is reflected through free and fair elections, are dismantled and stripped of their names and symbols, the ECI cannot absolve itself of responsibility or hide behind processes and practices. The BJP leadership in West Bengal has repeatedly claimed that, after the Assembly polls, there would be no existence of the Trinamool Congress as a party. The ECI's acts of omission and commission clearly suggest that it is acting in tandem with the interests of the BJP.

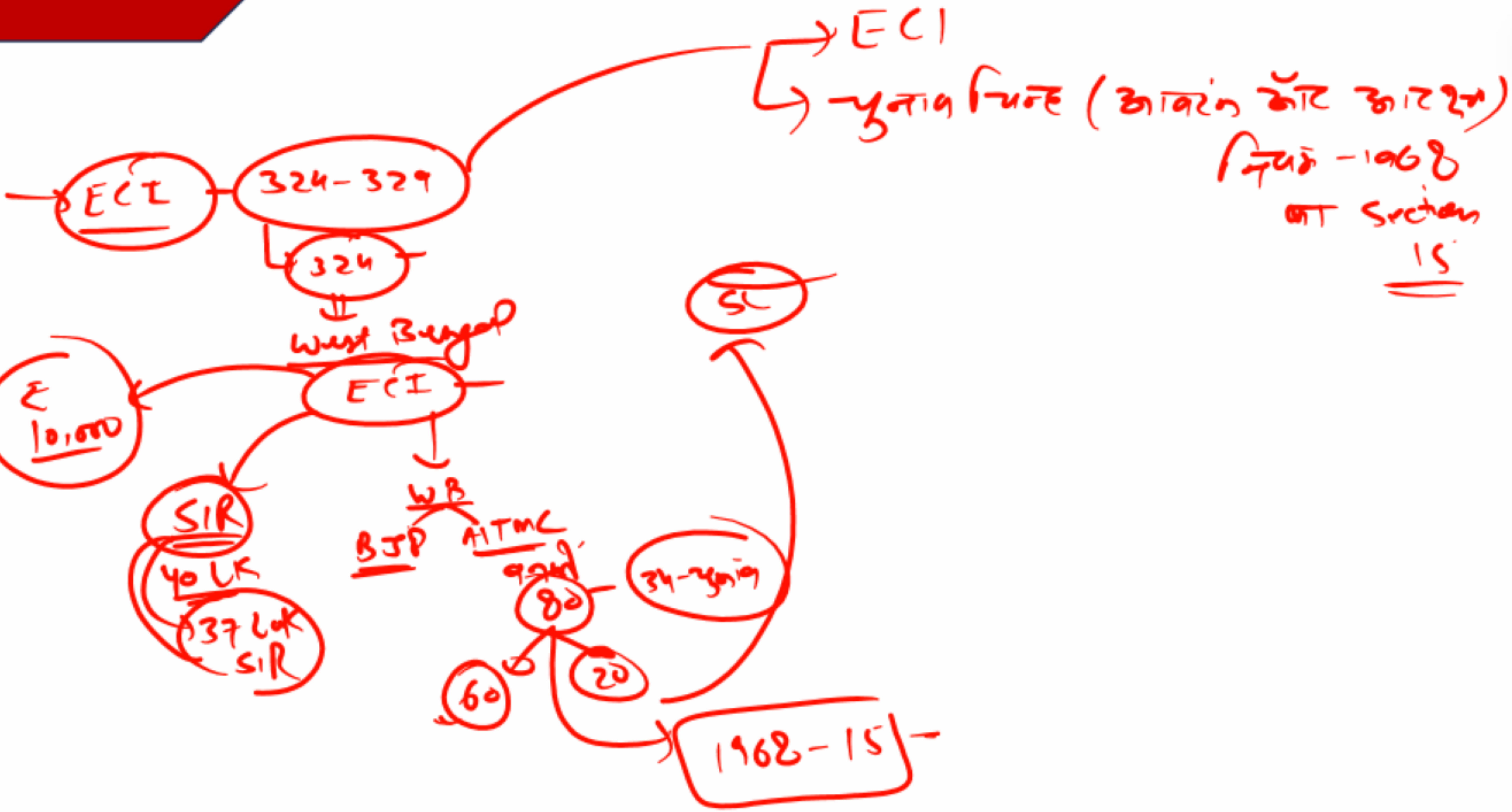

महत्वपूर्ण तथ्य

- **चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 [Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968]** भारत में चुनाव चिन्हों के आवंटन और राजनीतिक दलों के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है।
- इसे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा **अनुच्छेद 324** और **चुनाव संचालन नियम, 1961 (Conduct of Elections Rules, 1961)** के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके जारी किया गया था।
- इस आदेश के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. राजनीतिक दलों का वर्गीकरण (Classification of Parties)

- इस आदेश के तहत भारत के सभी राजनीतिक दलों को तीन वर्गों में बांटा गया है:
- **राष्ट्रीय दल (National Parties):** इन्हें एक स्थाई चुनाव चिन्ह मिलता है, जो पूरे देश में इन्हीं के लिए आरक्षित (Reserved) रहता है।
- **राज्य स्तरीय दल (State Parties):** इन्हें उस विशिष्ट राज्य में एक स्थाई चुनाव चिन्ह मिलता है जहाँ ये मान्यता प्राप्त हैं।
- **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल (Registered Unrecognized Parties):** इनके पास कोई आरक्षित चुनाव चिन्ह नहीं होता। इन्हें चुनाव आयोग की 'मुफ्त प्रतीकों' (Free Symbols) की सूची में से चुनाव चिन्ह चुनना पड़ता है।

2. चुनाव चिन्हों का वर्गीकरण

- चुनाव चिन्हों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:
- **आरक्षित प्रतीक (Reserved Symbols):** ये केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होते हैं।
- **मुक्त प्रतीक (Free Symbols):** यह उन चुनाव चिन्हों की एक सूची होती है जो किसी दल के लिए आरक्षित नहीं हैं। इन्हें निर्दलीय (Independent) उम्मीदवारों और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों को आवंटित किया जाता है।

3. पार्टी में विभाजन या विलय पर निर्णय (पैराग्राफ 15)

- इस आदेश का **पैराग्राफ 15 (Paragraph 15)** सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण भाग है:
- जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में विभाजन (Split) होता है और दो या दो से अधिक गुट 'असली पार्टी' होने का दावा करते हैं, तो निर्वाचन आयोग इसी पैराग्राफ 15 के तहत फैसला सुनाता है।
- आयोग पार्टी के संगठनात्मक ढांचे (Organizational Wing) और विधायी ढांचे (Legislative Wing - सांसद/विधायक) में बहुमत का परीक्षण करके असली पार्टी और चुनाव चिन्ह का निर्धारण करता है।
- यदि स्थिति स्पष्ट न हो या मामला जटिल हो, तो आयोग चुनाव चिन्ह को **फ्रीज (जब्त)** भी कर सकता है और दोनों गुटों को नए नाम व नए 'फ्री सिंबल' आवंटित कर सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

4. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का दर्जा देने के मानदंड

- इस आदेश में विशिष्ट शर्तें दी गई हैं जिनके आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलता है:
- **राज्य स्तरीय दल (State Party):** राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट और 2 सीटें, या कुल सीटों का 3% प्राप्त करना (अन्य शर्तों में से एक)।
- **राष्ट्रीय दल (National Party):** कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होना, या लोकसभा में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से 2% सीटें जीतना।

महत्वपूर्ण तथ्य

At UN summit, Jaishankar calls for reformed multilateralism

Press Trust of India
UNITED NATIONS

India has co-sponsored an inaugural multilateralism summit at the UN "at a time when the global order is under stress", as New Delhi asserts that more participative deliberations and transparent decision-making are overdue.

External Affairs Minister S. Jaishankar on Monday co-chaired the first-ever 'Partners for Multilateralism, International Law, Peace & Prosperity (P4M)' Summit held on the margins of the high-level 81st session of the UN General Assembly, along with leaders of Australia, Barbados, Brazil, Canada and Kenya.

"India is glad to join as a co-sponsor. We meet at a time when the global order is under stress," Mr. Jaishankar said in his remarks at the summit held in the UN headquarters.

He said that for some decades, the world had witnessed a steady rebalancing, which was a long-expected structural evolution.

"However, extreme competition, geopolitical tensions and actual conflicts have given this an entirely different character. If left unchecked, it would call into question the very spirit of international cooperation, and that is why it is so essential that multilateralism asserts itself strongly at this juncture," he said.

S. Jaishankar greets European Council President António Costa at the first ever P4M summit in New York on Monday. @DRSJAISHANKAR/X

He told the summit that where ongoing conflicts were concerned, specific dimensions could be addressed even while nations strived for a broader peace. "The '4F' crisis of fuel, food, fertilizer and finance cannot be left to itself. When new capabilities and concerns arise, there is a very powerful case for frameworks and guardrails. Where there is a threat of chokepoint dominance and disruption, de-risking and diversifying must be encouraged." "And where there is a compelling cause or a powerful case, the like-minded must have the confidence to come together," he said.

He was joined by the summit's cosponsors – President of the European Council António Costa, President of Kenya William Ruto, Australian Prime Minister Anthony Albanese, Barbados Prime Minister Mia Mottley, Brazilian Minister of Foreign Affairs Mauro Vieira and Canadian Permanent Representative David Lametti, who read remarks on behalf of Canadian Prime Minister Mark Carney.

He stressed that multilateralism would be best served when international law, rules and norms were scrupulously observed. He said, "For multilateralism to forge ahead, its advocacy and its practice must both be strengthened. Reformed multilateralism is therefore essential. More participative deliberations and more transparent decision-making are both overdue."

Packed schedule for Jaishankar at UN as India campaigns for Security Council spot

Suhasini Haidar
NEW DELHI

India on Monday joined the Partnership for Multilateralism, endorsing the "non-superpower" grouping originally launched by the European Union (EU), Brazil, Canada and Kenya, and became an additional co-sponsor of the initiative along with Australia and Barbados.

The meeting of the grouping, called P4M, which is expected to build support for the United Nations and multilateralism, was one of several bilateral and multilateral meetings External Affairs Minister S. Jaishankar took part in as he and the Indian delegation navigate a tough task list this week at the United Nations General Assembly (UNGA). On top of Mr. Jaishankar's agenda, this year is to garner support for India at next year's election for the United Nations Security Council (UNSC) non-permanent membership for the 2028-2029 period.

Within a few hours of landing in New York on Monday (September 21), Mr. Jaishankar met with Foreign Ministers from France, Ecuador, Slovakia, Hungary, Ukraine, Moldova, and Switzerland. He also met the President of Naoero (Nauru), participated in the P4M meeting, had another meeting with EU ministers, and attended an India-Visegrad group meeting with the Central European nations of Poland, Hungary, Slovakia and Czechia. On Tuesday he began his meetings with the 33-member Community of Latin American and Carribbean States (CELAC).

The meetings with European leaders, as well as expected meetings this week with his counterparts from the United States and Canada, are also expected to prepare for Prime Minister Narendra Modi's upcoming visits to Brussels, Miami and Ottawa in December. Officials say the rest of the External Affairs Minister's schedule this week – he is expected to remain in New York until he addresses the General Assembly on Saturday – will be equally packed for multiple reasons.

UNSC push

India has thus far been elected to the UNSC eight times, and on most occasions, has been the single name put forward for the Asia-Pacific group. However, this time, Tajikistan has also launched its candidature for the seat, and unless New Delhi can ensure a compromise, convincing the Tajik government to step aside in exchange for support for a future election, this will turn into a contest for the Asian seat.

As a result, all eyes will be on any meeting between Mr. Jaishankar and the Tajikistan Foreign Minister, Sirojiddin Muhriddin. In addition, Mr. Jaishankar's meetings with Ministers from other Central Asian countries, as well as from other parts of the Global South, will also be watched for any announcements of support for India's candidature. On the sidelines of the SCO Summit in Bishkek earlier this month, Mr. Modi held a meeting with Tajikistan President Emomali Rahmon. However, External Affairs Ministry officials said they could not confirm whether Mr. Modi had received any assurance from Mr. Rahmon regarding the UNSC seat.

महत्वपूर्ण तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के **81वें सत्र (UNGA 81st Session)** का विवरण निम्नलिखित है:
- **स्थान (Venue):** संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (UN Headquarters), न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)।
- **तिथि / अवधि (Dates):**
    - महासभा सत्र का औपचारिक शुभारंभ: **8 सितंबर 2026**।
    - उच्च-स्तरीय सामान्य बहस (High-Level General Debate): **22 सितंबर से 28 सितंबर 2026**।
    - यह सत्र पूरे एक वर्ष तक (सितंबर 2027 तक) चलेगा।
- **अध्यक्ष (President/Chairman): खलीलुर रहमान (Khalilur Rahman)**। वे बांग्लादेश के विदेश मंत्री और अनुभवी राजनयिक हैं।
- **मुख्य विषय (Theme): "Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers for All"** *(विश्वास की पुनर्बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन: एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए परिणाम दे)*।

- **Partners for Multilateralism (P4M) – *अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति (International Relations)***
- हाल ही में (21 सितंबर 2026 को UN General Assembly के 81वें सत्र के दौरान) विभिन्न देशों के नेताओं ने **P4M (Partners for Multilateralism)** नाम से एक नई वैश्विक पहल की शुरुआत की है।
- **उद्देश्य:** इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति, जलवायु परिवर्तन, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और व्यापार में बहुपक्षवाद (Multilateralism) को मजबूत करना है।
- **प्रमुख नेता:** इस पहल में कनाडा, ब्राजील, केन्या, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय परिषद के राष्ट्राध्यक्ष व प्रधानमंत्री शामिल हैं।
- **स्वरूप:** यह कोई नया प्रशासनिक ढांचा (bureaucratic block) नहीं है, बल्कि UN और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों को समर्थन देने के लिए एक खुला और लचीला नेटवर्क है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **CELAC** का पूरा नाम **Community of Latin American and Caribbean States** (लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई राज्यों का समुदाय) है।
- इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. CELAC क्या है?

- **अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन:** यह लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के **33 स्वतंत्र देशों** का एक क्षेत्रीय ब्लॉक (Regional Block) है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना वर्ष **2010** में (कारकास, वेनेजुएला में शिखर सम्मेलन के दौरान) हुई थी और आधिकारिक तौर पर इसने **2011** में काम करना शुरू किया।

2. इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

- **क्षेत्रीय एकीकरण (Regional Integration):** सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- **समान मंच:** इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और कनाडा के प्रभाव के बिना केवल लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों को वार्ता के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। (ध्यान दें: *Organization of American States - OAS* में अमेरिका और कनाडा भी शामिल हैं, जबकि CELAC में ये दोनों शामिल नहीं हैं)।
- **वैश्विक पहचान:** अंतर्राष्ट्रीय मंचों (जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ या चीन) के साथ बातचीत में पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना।

3. प्रमुख विशेषताएँ

- **सदस्यता:** दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं।
- **निर्णय प्रक्रिया:** CELAC में सभी निर्णय सर्वसम्मति (Consensus) के आधार पर लिए जाते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Trump, Greenland and Denmark sign agreement in bid to end Arctic standoff

Reuters
UNITED NATIONS

U.S. President Donald Trump and the leaders of Greenland and Denmark signed an agreement on Tuesday that permits a larger U.S. military presence on Greenland and may resolve a standoff over the strategically located and mineral-rich island.

The agreement, signed during Mr. Trump's visit to the UN General Assembly in New York, stops short of Mr. Trump's demand that the U.S. annex Greenland as a U.S. territory to head off the growing Arctic presence of Russia and China.

But the deal does codify a greater U.S. military presence on the icy territory, an option that emerged as Greenland leaders argued against a complete U.S. takeover.

Mette Frederiksen and Jens-Frederik Nielsen attend a press meet, after a security deal with the U.S. is signed, on Tuesday. REUTERS

A text of the deal released after the event said the U.S. can establish a "Golden Dome" defence system in Greenland as a shield against ballistic missile threats. The shortest route from Europe to North America runs via the Arctic island, which is the location of the northernmost U.S. military base.

In his speech to the assembled world leaders at the UN before the signing ceremony, Mr. Trump said the agreement gives the U.S. "permanent control over security and all other needs on that territory".

"No U.S. adversary will ever be permitted to establish a military presence in Greenland any more, or make sensitive investments there without our express written approval," Mr. Trump said.

Mr. Trump signed the agreement along with Danish Prime Minister Mette Frederiksen and Greenland Prime Minister Jens-Frederik Nielsen in a trilateral ceremony after Mr. Trump gave his UN speech.

Ms. Frederiksen described the agreement as a deal that can "last forever" and said it underlines the importance of the NATO alliance and respects Greenland's right to self-determination.

Mr. Nielsen emphasised the importance of NATO in the Arctic region. "We believe that it is vital to keep NATO strong, also in the Arctic, where the alliance has a key role to play," he said.

Greenland, a former colony and now a semi-autonomous territory of the Kingdom of Denmark, sits between the Arctic and North America and holds vast energy resources.

महत्वपूर्ण तथ्य

अमेरिका, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच हुए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते (Trilateral Security Agreement)

1. मुख्य विषय (Core Topic)

- अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन (Mette Frederiksen) और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन (Jens-Frederik Nielsen) ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसका उद्देश्य रणनीतिक (strategically located) और खनिजों से समृद्ध (mineral-rich) ग्रीनलैंड द्वीप पर अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को बढ़ाना और आर्कटिक क्षेत्र में चल रहे तनाव/गतिरोध को समाप्त करना है।

2. प्रमुख बिंदु (Key Points)

- **ग्रीनलैंड का विलय नहीं:** पहले ट्रम्प ग्रीनलैंड को अमरीकी क्षेत्र के रूप में मिलाने (annexation) की माँग कर रहे थे, लेकिन इस समझौते में विलय के बजाय केवल अमरीकी सैन्य उपस्थिति (US military presence) बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- **'गोल्डन डोम' रक्षा प्रणाली (Golden Dome System):** समझौते के तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में एक "गोल्डन डोम" रक्षा प्रणाली स्थापित कर सकता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से सुरक्षा प्रदान करेगी।
- **चीन और रूस पर रोक:** अमरीकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि किसी भी विरोधी देश (जैसे चीन या रूस) को ग्रीनलैंड में सैन्य उपस्थिति बनाने या अमेरिका की लिखित अनुमति के बिना संवेदनशील निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- **नाटो (NATO) और आत्मनिर्णय का अधिकार:** डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने कहा कि यह समझौता नाटो गठबंधन की मजबूती को रेखांकित करता है और ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय (self-determination) के अधिकार का सम्मान करता है।
- **संक्षेप में:** ग्रीनलैंड के पूर्ण अधिग्रहण (takeover) के बजाय, अमेरिका ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता किया है जिससे उसे ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने, सुरक्षा नियंत्रण रखने और रूस व चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने का कानूनी अधिकार मिल गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

— Asian Games

Women in Blue retain gold in emphatic fashion

Smriti and Shafali provide the perfect launchpad with a scintillating 99-run opening stand; Richa's cameo powers India to a daunting total before the spin quartet blows away the Lankans

ASIAN GAMES

Uthra Ganesan
NAGOYA

The Indian National anthem played for the first time at the Aichi-Nagoya Asian Games on Tuesday.

A blistering opening partnership followed by a cracking innings and spin choke-hold ensured the country its first gold at the Games. Harmanpreet Kaur's women retained their title in commanding fashion with a 147-run victory against Sri Lanka in the final at the Korogi Athletics Park in Nisshin.

Chasing a massive 217-run target, Sri Lanka folded up for 69 in 15.4 overs, stumbling early on and never finding their footing as Deepti Sharma and Co. didn't allow any breathing space to the Sri Lankan batters on a small ground.

The damage with the ball was initiated, as with the bat, by Shafali Verma who sent back Imesha Dulani and Hasini Perera in consecutive overs to reduce the Islanders to 30 for two inside five overs. She didn't bowl again but the collapse had begun and when Sri Lanka skipper Chamari Athapaththu was caught by Bharti Fulmali at long-off off Deepti, with the scoreboard reading 43 for three, it was all but over.

Chamari was the top-scorer for Lanka with 29 (21b, 5x4), one of only three batters to reach double digits in a line-up that had three ducks. Deepti scalped three while Shreyanka Patil and Shree Charani got two wickets each as Sri Lanka ended with yet another silver from the continental showpiece after the last edition in Hangzhou.

Earlier, having elected to bat, the Indians continued in the same vein as in the Asia Cup final nine days ago. Shafali (48, 29b, 3x4, 3x6) and Smriti Mandhana (79, 45b, 5x4, 7x6) were in imperious form. The two added 99 in the first 10 overs, scoring at over 150 strike rate each. Shafali, trying to go for a reverse sweep, failed to clear the infield, and missed out on a half-century.

Richa Ghosh's unbeaten 22-ball 49 (6x4, 3x6) was the icing on the cake and propelled the total beyond 200 after Harmanpreet fell for 19. Smriti's sublime but equally destructive knock was the foundation of India's daunting 216 for three.

In the morning, Pakistan captain Fatima Sana's 30-ball 45 and Umm-e-Hani's three for 10 helped the team clinch the bronze with a 31-run victory against Bangladesh in the playoff.

The scores (final): India 216/3 in 20 overs (Shafali 48, Smriti 79, Richa 49 n.o.) bt Sri Lanka 69 in 15.4 overs (Chamari 29, Shafali 2/3, Deepti 3/6, Shreyanka 2/9, Shree Charani 2/13).

Toss: India.

Undisputed champions: The Indian women asserted their class at the continental extravaganza with a thumping 147-run win in the final. R.V. MOORTHY

'We will have this gold medal with us forever'

Uthra Ganesan
NAGOYA

Harmanpreet Kaur has done what no one else can claim to have done, or may do for a while – be the captain of an Asian Games-winning cricket team twice in a row. And she has the medals to prove it.

Firm favourite to defend its title at the Korogi Athletics Park even before the team landed in Tokyo, and coming after the high of clinching the Asia Cup, the gulf between the Women in Blue and the rest was far too wide.

"As cricketers, we always wanted to be a part of the Asian Games or Commonwealth Games or Olympics, because otherwise we only play cricket tournaments. We did not know the value of what a medal actually means.

"We are lucky to have done it twice now because the cricketers before us did not have this. Now we can also frame two medals back home because when we win a trophy, it feels good but it goes to the BCCI office. This is something we will have with us forever... this is ours," Harmanpreet said on Tuesday.

That the team's gold was also the first for India at the ongoing Games only made it extra special.

"Our aim was to win gold and see the national flag high... [we] talked about the national anthem playing. But we didn't know we would be the first to experience it here. I am sure that we have opened the golden gates".

Joy! Harmanpreet added another feather to her cap. R.V. MOORTHY

महत्वपूर्ण तथ्य

- एशियन गेम्स 2026 (आइची-नागोया) में भारत ने अब तक कुल 7 पदक जीत लिए हैं, जिसमें स्वर्ण (गोल्ड) मेडल भी शामिल है।

वर्तमान मेडल विवरण (2026)

- **गोल्ड मेडल:** हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को फाइनल में 147 रनों से हराकर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है।
- **अन्य पदक:** इसके अलावा निशानेबाजी (शूटिंग) और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए हैं।

पदक का प्रकार	**संख्या**
स्वर्ण (Gold)	1
रजत (Silver)	4
कांस्य (Bronze)	2
कुल पदक	7

रजत पदक (Silver Medals) — कुल 4

- निशानेबाजी (Shooting) में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को चारों रजत पदक दिलाए हैं:
- **इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद:** महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में देश को पहला रजत पदक दिलाया।
- **इलावेनिल वलारिवन:** टीम स्पर्धा के बाद उन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल के व्यक्तिगत (Individual) इवेंट में भी रजत पदक पर निशाना साधा।
- **रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों:** पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में चीनी टीम को कड़ी टक्कर देते हुए रजत पदक हासिल किया।
- **हिमांशु ढिल्लों:** पुरुष 10 मीटर एयर राइफल के व्यक्तिगत इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता।

महत्वपूर्ण तथ्य

कांस्य पदक (Bronze Medals) — कुल 2

- भारत ने निशानेबाजी के साथ-साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी ऐतिहासिक सफलता हासिल की है:
- **रुद्रांक्ष पाटिल:** पुरुष 10 मीटर एयर राइफल के व्यक्तिगत इवेंट में देश के लिए कांस्य पदक जीता।
- **सुचिका तरियाल:** मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) के महिला ट्रडिशनल -60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुँचकर कांस्य पदक अपने नाम किया। यह एशियन गेम्स के इतिहास में MMA में भारत का अब तक का पहला पदक है।

Home Assignment

World Rhino Day

Dada Saheb Phalke Award - 2024

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Question):

प्रश्न: 'नीलाकुरिंजी' (Strobilanthes kunthiana) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह फूल प्रत्येक 12 वर्षों में केवल एक बार खिलता है।
2. यह मुख्य रूप से पूर्वी घाट के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है।
3. नीलगिरी पहाड़ियों का नाम 'ब्लू माउंटेन्स' इसी फूल के खिलने के कारण पड़ा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

Overview

- Ayurveda Day
- Women Farmer
- India-US Trade deal
- Kasturiranjan Report
- Neelkurunji
- Nasha Mukt Bharat
- PM-SSY
- AITMC
- UNGA Summit
- Greenland – USA – Denmark Agreement
- Asia Games

P4M
CELAC

Thank You

Result Mitra

Thanks For Watching

Follow us for more Updates

Learn Share Grow Together ♡

Better Students Brighter Tomorrow

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

DISCIPLINE

CONSISTENCY

SUCCESS

Small Steps Big Results

Stay Connected